

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI NARAIN DASS GUPTA (NCT of Delhi): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRIMATI VIJILA SATHYANTH: Sir, the same thing is prevailing in the Indian Postal Services also. ...(*Interruptions*)...

MR. CHAIRMAN: The Minister is responding.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चन्द गहलोत): सभापति महोदय, जैसे ही हमें उनके धरने पर बैठने की सूचना मिली और रेलवे में भर्ती से संबंधित समस्याओं को लेकर वे धरने पर बैठे, तो मैंने स्वयं माननीय रेल मंत्री, पीयूष गोयल साहब से बात की। हम दोनों ने विचार-विमर्श किया। फिर मेरे विभाग के अधिकारी भी उनके पास बातचीत करने के लिए गए और रेलवे के अधिकारी भी उनके पास बातचीत करने के लिए गए, परन्तु तालमेल नहीं बैठने के कारण मामला हल नहीं हो पाया। मैं फिर रेल मंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वे इस समस्या का शीघ्रातिशीघ्र समाधान करने का प्रयास करें।

MR. CHAIRMAN: Ms. Saroj Pandey; not present. Shri Digvijaya Singh.

Need to extend compensation of GST to States

श्री दिग्विजय सिंह (मध्य प्रदेश) : माननीय सभापति महोदय, इस सदन में हम सब राज्यों के प्रतिनिधि के रूप में चुन कर आए हैं। जीएसटी कानून के अंतर्गत राज्यों को वर्ष 2022 तक compensation देने का प्रावधान है। अगस्त से राज्यों को अनुदान नहीं मिल रहा है। इसके कारण राज्यों को खर्च चलाने में दिक्कत आ रही है, उनको कर्ज लेना पड़ रहा है। इस वर्ष बाढ़ के कारण बहुत बड़े पैमाने पर फसलों का नुकसान हुआ है, उसमें मुआवजा बाँटने में दिक्कत आ रही है। केन्द्र सरकार ने भी संभावना से कम जीएसटी आने के कारण समय पर compensation देने में असमर्थता व्यक्त की है। मेरा शासन से अनुरोध है कि राज्यों को जीएसटी compensation शीघ्र रिलीज करें, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति में काफी दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही मेरा यह भी अनुरोध है कि जो compensation देने की समय-सीमा मार्च, 2022 तक है, उसे मार्च, 2027 तक किया जाए। आपसे यह भी

अनुरोध है कि चूँकि यह राज्यों की वित्त स्थिति का मसला है, इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है और लीडर ऑफ दि हाउस से अनुरोध है कि माननीय वित्त मंत्री जी के द्वारा, चूँकि कल सेशन का आखिरी दिन है, इसलिए कल ही जीएसटी के अनुदान को कब और कितना देंगे, उसके बारे में स्टेटमेंट आना चाहिए, धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। Appropriation Bill भी है, मेरे ख्याल से हो सकता है।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, this is a very important issue.

MR. CHAIRMAN: That is why I allowed it.

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, they have not been paid for four months.

...(Interruptions)...

MR. CHAIRMAN: No, no; please.

श्री राजमणि पटेल (मध्य प्रदेश): महोदय, मैं स्वयं को इस विषय से संबद्ध करता हूँ।

DR. BANDA PRAKASH (Telangana): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI SUBHASISH CHAKRABORTY (West Bengal): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. AMAR PATNAIK (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

DR. SASMIT PATRA (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI NARAIN DASS GUPTA (NCT of Delhi): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

SHRI BHASKAR RAO NEKKANTI (Odisha): Sir, I too associate myself with the matter raised by the hon. Member.

**Need for conservation and promotion of the Bateshwar Temple
Complex in Madhya Pradesh**

श्री शिव प्रताप शुक्ल (उत्तर प्रदेश): मान्यवर, हमारे देश में सांस्कृतिक धरोहर के रूप में अनेक मंदिर और इमारतें हैं। ये कोई एक जगह नहीं हैं, बल्कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, हर जगह हैं। ऐसे मंदिरों की संरक्षण की हमें अत्यंत आवश्यकता है और मैं समझता